



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 कार्तिक 1943 (श10)

(सं0 पटना 890) पटना, वृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2021

एस0ओ0 160 दिनांक 28 अक्टूबर 2021—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, 1974) की धारा-9 की उपधारा (1) तथा (3) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम 33, 1989) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में, बिहार राज्यपाल ने -

(i) पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन मामलों के त्वरित विचारण के लिए निम्नांकित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) अभिहित करने की कृपा की है, जिसकी अधिकारिता संबंधित जिले की स्थानीय सीमाएँ होंगी:-

क्रम सं0	न्यायमंडल का नाम	मुख्यालय	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का नाम
1	पटना	पटना	श्री त्रिलोकी दुबे
2	गया	गया	सुश्री नम्रता तिवारी
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	श्री पुनीत कुमार गर्ग
4	बेगूसराय	बेगूसराय	श्री अरूण कुमार
5	भागलपुर	भागलपुर	श्री रोहित शंकर

(ii) एतद् द्वारा उपर्युक्त अंकित अनन्य विशेष न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम] के न्यायालय के रूप में अभिहित किए जाते हैं।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन उद्भूतवादों के विचारण से संबंधित विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना दिनांक-10.02.1995, अधिसूचना सं0-356/जे0 दिनांक-15.01.2015 तथा अधिसूचना सं0-7102/जे0 दिनांक-27.11.2017 उपर्युक्त जिलों के मामले में, एतद् द्वारा उपर्युक्त हद तक संशोधित की जाती है।

(iv) उपर्युक्त 5 (पाँच) जिलों में संबंधित न्यायमंडल के वरीयता क्रम में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों के समक्ष लंबित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित सभी मामले/विचारण तदनुसार उपर्युक्त संबंधित अभिहित अनन्य विशेष न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे।

(v) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट0-01/2014/5817/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
फूल चन्द्र चौधरी,  
सरकार के सचिव।

27 अक्टूबर 2021

एस0ओ0 160 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट0-01/2014/5817/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
फूल चन्द्र चौधरी,  
सरकार के सचिव।

### ***The 27th October 2021***

S. O.160 dated 28th October 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section-9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974) and section-14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act 33 of 1989), in modification of all the previous orders and notifications issued on this subject, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, the Governor of Bihar is pleased to -

(i) Designate the Courts of the following Additional District and Sessions Judge as exclusive special court under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in the districts of Patna, Gaya, Muzaffarpur, Begusarai and Bhagalpur for speedy trial of cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, the Jurisdiction of which will be the respective local limits of the concerned district:-

Sl. No.	Name of the Judgeship	Headquarters	Name of Addl. District and Sessions Judge
1	Patna	Patna	Sri Triloki Dubey
2	Gaya	Gaya	Ms. Namrata Tiwary
3	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Sri Puneet Kumar Garg
4	Begusarai	Begusarai	Sri Arun Kumar
5	Bhagalpur	Bhagalpur	Sri Rohit Shankar

(ii) The aforesaid Exclusive Special Courts are hereby designated as Courts of Additional District and Session Judge [Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act].

(iii) The Notification dated 10.02.1995, notification no.-356/J dated-15-01-2015 and notification no.-7102/J dated 27.11.2017 of Law Department, Bihar, Patna, with respect to trials of the cases arising under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 for the above said districts is accordingly hereby amended to the extent indicated above.

(iv) All Such cases/trials relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, pending before the Court of Additional District and Sessions Judge 3rd in seniority of the concerned Judgeship in the above said five districts, would accordingly stand transferred to the concerned aforesaid designated Exclusive Special Courts

(v) This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(File No.-A/Act-01/2014/5816/J)  
By Order of the Governor of Bihar,  
**PHOOL CHANDRA CHOUDHARY,**  
*Secretary to Government of Bihar.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 890-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>